RAJYA SABHA

Friday, the 6th May, 1988/16 Vaisakha 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock, The **Deputy Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Writing off debts of farmers

*181. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the demands made by different farmers organisations and political parties for writing off the entire debts of farmers in the country; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) Demands have been raised from time to time for writing off the loans of farmers in full or in part, taken from institutional sources.

(b) Already there are adequate arrangements for providing relief to loanee farmers affected by natural calamities. There have also been recently liberalised. There is, therefore, no need for any blanket write off of institutional loans.

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया, 1980 के इस किसान दशक में किसानों की ऋण-माफी की न्यायोचित एवं प्रभावशाली मांग को सरकार ने बड़ी निर्दयता से ठुकरा दिया है । प्राकृतिक आपदाओं और किसानों को दी गई छुट-पुट छूट को पर्याप्त व्यवस्था मानना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । किसानों पर ऋणों के बढ़ते और असहाय बोझ का कारण केवल प्राकृतिक आपदायें नहीं हैं, उत्पादन खर्च का आधारित मूल्य न देने वाली अर्थ-व्यवस्था, कृषि और उससे बनी औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों की भंयकर विषमता से निर्मित शोषण, आदि अनेक कारण इसकी जड़ में है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसानों पर ऋण का कुल बोझा, ऋण की वापसी की किसानों की शक्ति तथा संभावना, उसके निराकरण के उपाय और बोझे के कारण, क्या इन सब का अध्ययन करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के आधिपत्य में केन्द्र सरकार एक आयोग का गठन करने की किसानों की मांग पर विचार करेगी ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया माननीय सदस्य ने । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री दीपेन घोष : भाषण केवल मंत्री लोगों के लिये ही है ।

श्री भजन लाल : नहीं, नहीं, भाषण देना चाहिये । लेकिन माननीय सदस्य ने सवाल कम पूछा है, भाषण ज्यादा दे दिया है, इसलिये मैं कह रहा हूं, और कोई बात नहीं है । इन्होंने दो बातें कहीं सारी बातों हे जो मैंने सार निकाला । एक तो इन्होंने कहा कि अकेला प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नहीं किसान को भाव भी पूरा ठीक नहीं मिला और इस वजह से भी किसान कर्जे में दबा हुआ है। इसके बारे में उपसभापति महोदया, मैंने परसों बहुत तफसील के साथ दो घंटे तक पूरी जानकारी सदन में दी थी कि बकायदा भाव तय करते समय एक-एक बात का हिसाब लगाकर के, कि किसान का कितना खर्च आता है, कितनी मजदूरी लगती है, कितनी लेबर लगती है, घर की लेबर तक का, सारा हिसाब लगाकर के भाव तय करते हैं और बकायदा लाभकारी मूल्य किसान को देते हैं । दूसरा, इन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा कमीशन बनाने की योजना सरकार की है तथा किसानों का जो ऋण है वह माफ किया जायेगा ? यह मांगें बार बार अपोजीशन उठाती रही है इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन ऐसी मांग से आप सस्ती लोकप्रियता लेने की कोशिश करते हैं, चीप-पापुलरिटी और आपके हाथ में जब देश की बागडोर आई थी एक दफा क्या उस समय माफ कर दिये थे कर्जे लोगों के आपने

आज ये मांग करते हैं कि कर्जे माफ होने चाहियें । आप जानते हैं कर्जे माफ करना देश के अन्दर शुरू हो गया तो सारा... (**व्यवधान**)...एक मिनिट कृपा करके सुनियेगा अच्छी तरह से ।

श्री दीपेन घोष : भाषण का जवाब भाषण में है ।

श्री भजन लाल : भाषण नहीं है । मैं जवाब दूंगा तफसील से ।... (**व्यवधान**) ... अभी-अभी आपकी सेवा में हाजिर हो रहा हूं ..(**व्यवधान**).. नहीं नहीं खास तौर से उनकी सेवा में आपकी सेवा में नहीं । सुब्रह्मण्यम स्वामी जी बहुत जाते हैं हरियाणा में इसलिये मैं कह रहा हूं । पंजाब में भी जाते हैं स्वर्ण-मंदिर तक पहुंच गये हैं .. (**व्यवधान**)..

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने सी. आई.बी. मेरे पीछे लगाया है क्या ?

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा कीजिये । उपसभापति महोदया, अभी साल में तकरीबन 12 साढ़े 12 हजार करोड़ का लोन जोकि किसान से सीधा ताल्लुक रखता है – ट्रैक्टर के लिये ट्यूब वैल के लिये, खाद, बीज और हल के लिये है, किसान को वितरित किया जाता है । कोई भी सरकार लोन माफ नहीं कर सकती है, रियायत दे सकती है और रियायत देने की हमने कोशिश की है । ब्याज में छूट दी है । सूखा पड़ने पर जहां वसूली 6 महीने से लेकर डेढ़ साल में की जानी थी उसे 7 से 10 साल में की है ब्याज की दरें भी कम की हैं । जैसा अभी सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने कहा, इसलिये मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि देवीलाल जी लोगों से कहते रहे कि कर्जे माफ कर देंगे आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ और लोगों ने विश्वास कर लिया । मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों को इनवाइट करता हूं कि आफ हरियाणा में चलें । मैं आपको बाकायदा एअर कंडीशंड बस में ले जाऊंगा । वहां जाकर आप किसान से पूछिये कि उसकी हालत क्या है ? उन्होंने धोखा और गलत वायदे करके वोट लिये हैं ।

PROF. C. LAKSHMANNA: What is the reply?

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: It is not an election rally. Already you have failed.

श्री भजन लाल : महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऋण माफ करने की प्रथा बहुत गलत है और अगर एक बार यह प्रथा शुरू हो गयी तो कोई आदमी ऋण वापिस करने की सोचेगा ही नहीं इसलिये ऐसी प्रथा पर विचार करना बिल्कुल संभव नहीं है ।

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार किसी आयोग का गठन करेगी । जनता पार्टी में जितना हुआ, उस बारे में जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा भजन लाल जी जानते हैं । मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता । मैं आयोग के गठन के बारे में जानना चाहता हूं ।

उपसभापति : उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री भजन लाल : कमीशन बनाने का का कोई विचार नहीं है ।

श्री प्रमोद महाजन : उपसभापति महोदया, यह सरकार ऐसी है जो पहले संभावनाओं की जानकारी लेती है और फिर कमीशन की आवश्यकता तय करती है । साधारणतः उल्टा होता है । यह संभव है या नहीं है यह पता लगाने के लिये मैंने कहा था । किसान को लाभदायक मूल्य मिलता है, यह गलत है । यह सस्ती लोकप्रियता का प्रश्न नहीं है अंग्रेजों ने भी एक बार किसानों की हालत देख कर ऋण मुक्ति का कानून बनाया था । खैर आप करना नहीं चाहते । मैं अगला सवाल यह करना चाहता हूं कि जब तक आपको किसानों की पूर्ण ऋण मुक्ति के संबंध में ज्ञान और बोध नहीं होगा तब तक क्या आप किसानों को सभी फसलों के लिये, मैं सभी कह रहा हूं, बाद में उत्तर में कोई गड़बड़ी न हो और पूर्ण फसल बीमा योजना, मैं

पूर्ण फसल बीमा योजना कह रहा हूं, फसल बीमा योजना नहीं– सभी फसलों के लिये पूर्ण फसल बीमा योजना तत्काल लागू करने की किसानों की मांग कब तक स्वीकार की जायेगी ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, इस फसल बीमा योजना का इससे तो ताल्लुक है नहीं, लेकिन मैं फिर भी सदन को यह बताना चाहता हूं किसानों को लाभकारी मूल्य हमने दिया है । एक बात कमीशन खाने की कही गयी तो यह तो सबसे ज्यादा उनकी आदत है ही । दूसरा सवाल इन्होंने किया फसल बीमा योजना के बारे में, फसल बीमा योजना के बारे में जैसा कि मैंने हाउस में परसों बताया था कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो स्कीम है, वह कोई बहुत ठीक नहीं है । उसको हम उदार बनाने जा रहे हैं ताकि उससे सारे किसानों को लाभ मिल सके और सारे किसानों की फसल का बीमा किया जा सके चाहे कोई ऋण ले या नहीं ले । प्रीमियम हम उनसे ले लें और फिर उनकी फसल का बीमा कर दें । इस पर हम विचार कर रहे हैं । प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई है । 11 तारीख को ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होगी । हम चाहते हैं कि तहसील, ब्लाक और मंडल के बजाय गांव या पटवार सर्कल पर यूनिट बने ताकि किसानों को सही लाभ मिल सके ।

SHRI A. G. KULKARNI: Madam Deputy Chairman, may I know from the hon. Minister whether he is aware that various studies have been made apart from the Commission on Agricultural Costs and Prices? It is one of the Committees of Dr. Dandekar which has made a research on the imbalance between agricultural prices and manufacturing prices. It has been established now that the NDP in agriculture during the last 34 years, that is the Net Domestic Product has grown by .0074 per cent as against 2.48 per cent per capita of NDP in non-agriculture. This is one aspect.

Secondly, Mr. Minister, according to the 37th round of National Sample Survey, 1982, about the debt investment ratio in the rural family—I am only bringing it to you to come to an objective assessment there are about 93.6 million households in the rural areas and they owe cumulatively Rs. 61,923 million to the bank, to the private sahukars and everybody.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI A. G. KULKARNI: I am coming to the question. This is the parameter where you, as an Agriculture Minister, have to apply your mind. Again, the third assessment made by the Research Bureau is that input cost per one rupee worth of output has risen from 24 naya paisa to 34 naya paisa. In view of these three parameters mentioned by me for your kind consideration, what I want to know from you is the Government very recently in the Budget speech are reducing the input prices and they are helping the agricultural growth. I am aware of that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please put your supplementary.

SHRI A. G. KULKARNI: My question is coming. The solution is not the cheap gimmicks of writing off the loans. These are all populist gimmicks, cheap gimmicks for political purpose. Nobody is going to wipe out the loans. Nobody can do that. Even Kuber, who is called the moneylender of God cannot do that. Taking an objective view of the theoretical position of rural families and agrculturists, the process has to be accelerated. You have said that some Committee is going into it. Based on these three results, one is Dr. Dandekar's report second is the 37th round of NSS Debt Investment Ratio, wherein about 93.6 million households/families are owing Rs. 61927 million and the input cost is rising, what best and how best and how quick you can help the agricultural community because the whole of the country is being threatened by one of the agitations which is going to destablise any political process.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI A. G. KULKARNI: I want to draw the attention of the hon. Minister to this and what is his reply?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, कुलकर्णी जी ने बहुत ही अहम सवाल पूछा इसमें कोई दो रायें नहीं है । वह हमारे बहुत सीनियर मैंबर है, पुराने मैंबर हैं ।

SHRI A. G. KULKARNI: Madam, with this, I am denied all the correct reply. आप नालेजेबल हैं, आप ठीक जवाब दें

एक माननीय सदस्य : आप ज्ञानी हैं, नेलेजेबल नहीं हो सकते . . . **(व्यवधान)**

SHRI A. G. KULKARNI: That I am. I expect you to be knowledgeable.

ज्ञानी बनाना, ज्ञानी जी मत बनाना ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is a mark of respect for you. Why don't you accept that?

श्री भजन लाल : आप जब सवाल पूछते हैं तब हम आपसे सीखतें हैं, इसलिए कहा था मैंने ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : अच्छा, सीखिए ।

श्री भजन लाल : जो इन्होंने दो बातें मेन कहीं कि एक तो डाक्टर साहब की रिपोर्ट का सर्वे किया था या नहीं इसके अलावा भी सर्वे होता रहता है और डाक्टर साहब की रिपोर्ट भी देखी है जहां एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सारी बात को देखता है । इसके अलावा हमारे जो विशेषज्ञ हैं वे भी इस बात को देखते हैं कि किसान को क्या उचित मूल्य मिलना चाहिए, कितना उसका खर्चा आता है । आप जानते हैं देश में सवा नौ करोड़ परिवार जो खेती करते हैं, नौ करोड़ तीस लाख, जिनका खेती से गुजारा चलता है उनकी एक एक बात और आवश्यकता को देखते हैं और बकायदा क्रेडिट लोन उनको देते हैं और पहले बड़ी भारी कठिनाई थी कोई भी आदमी अगर उसकी खुद की जमीन है और काश्त करता है उसको तो जमीन गिरवी रख कर लोन मिल जाता था । मगर जिसके पास अपनी जमीन नहीं थी टेनेन्ट था उसे लोन लेने में बड़ी कठिनाई आती थी । उसके बाद इसको सरल करने के लिए प्रधान मंत्री ने बड़ा शानदार फैसला लिया । अब इंडिविज्यूल आदमी, अगर उसके पास जमीन नहीं भी है, पांच हजार का लोन ले सकता है अपनी खुद की गारन्टी के ऊपर अपनी सेल्फ गारन्टी के ऊपर, कोई जमानत देने की जरूरत नही चाहे उसके पास जमीन है या नहीं । परन्तु जमीन वाला भी जो काश्त करता है या टेनेन्ट है, वह भी ले सकता है ताकि उसको परेशानी न हो । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने जो बातें कहीं हैं इन सारी बातों को देखकर और एक एक बात की तह में जाकर ही किसान के हित की बात करते हैं । इस सरकार की नीति है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और जितना कुछ भी भला सरकार कर सकती है उतना करेगी, जैसी इसमें चेष्टा की गई है और आगे भी इससे ज्यादा ध्यान किसान का रखा जायेगा ।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी : उपसभापति महोदया, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के संबंध में जो भी जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं है । सवाल बहुत सीधा-सादा था कि मुख्तलिफ किसान संगठनों और राजनांतिक पार्टियों ने समय-समय पर जो मांग की है क्योंकि जो रिस्थिति देश में पैदा हो गई है सूखे वगैरह की वजह से किसान तबाह हो गये हैं, खेती खराब हो गई है और वे इस हालत में नहीं है आज कि कर्जा दे सकें, वापस कर सकें । इसलिये सरकार से वे मांग कर रहे हैं, कई जगह से, कई सालों से कि उनका जो ऋण है वह पूरी तरह से माफ हो । मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणी किसानों को सहायता देने के लिये पहले ही पर्याप्त व्यवस्थायें की गई हैं जिन्हें हाल ही में उदार भी बनाया गया हैं अतः संस्थागत ऋण को सामान्यतः पूर्ण रूप से माफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है । सवाल यह है कि क्या इन हालात में,

यह तमाम चीजें है ही, इसके बावजूद सरकार कोई योजना सोच रही है कि जो किसानों की बुरी हालत आज है वे कर्जा देने की, वापस करने की हालत में आज नहीं हैं। कई जगह तो यहां तक कि सुइसाइड कर रहे है, वे फांसी लगा रहे हैं और इन हालात में सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता से और मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह संभव नहीं है, यह गलत तरीका है, इसको माफ करने से एक परम्परा बन जायेगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब करोड़ों रुपया इंडस्ट्रियलिस्टस को माफ किया जा सकता है, तो किसानों को जो रात-दिन मेहनत करते हैं, सारे देश को खिलाते हैं, देश को बनाने में उनका हिस्सा है उनकी इस तकलीफ को दूर करने के लिये सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती। आपको इस सिलसिले में कोई कदम जरूर उठाना चाहिये। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि यह संभव नहीं है, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो किन हालत में उनके दर्द को दूर करने के लिये आप योजना बना रहे हैं।

श्री भजन लाल उपसभापति महोदया, फिर मैं वही बात कहूंगा कि थोड़ी सी तकलीफ होगी। मैंने तफसील से इसका जवाब अभी दिया था कि कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। जितनी फेसिलिटीज, जितनी रियायत दे सकते हैं सरकार ने देने की कोशिश की है। और जहां सूखा पड़ गया वहां स्पेशल रियायत दी गयी। जहां लगातार दो साल तक सूखा पड़ा वहां से सात साल में वसूली की जायेगी और जहां लगातार तीन साल सूखा पड़ा वहां से दस साल में वसूली की जायेगी। अगर ब्याज मूल से ज्यादा होगा तो ब्याज छोड़ दिया जायेगा और दुबारा ऋण लेने में भी उसके सामने कोई कठिनाई नही आयेगी। इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि कर्जा माफ होना चाहिए हर हालत में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आन्ध्र प्रदेश में आपकी पार्टी है, कर्नाटक में आपकी पार्टी है, बंगाल में आपकी पार्टी है तो क्या आप लोगो ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया?

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : किया है।

श्री भजन लाल : हो नहीं सकता। बड़ा कठिन काम है। हरियाणा में मेरे साथ चलिए वहां आपको लेकर चलता हूं वहां का एक भी किसान कह दे कि मेरा कर्जा माफ हो गया तो जो सजा आप देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। आप सारी बातें गुमराह करने की कर रहे है, झूठे वायदे करने की बात करते हैं। हर सियासी आदमी हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : जो करने की बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : यह हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो सारा मुल्क एक साल में दिवालिया हो जायेगा। फिर कौन देगा कर्जा? आप आज एक का कर्जा माफ करेंगे तो कल रिक्शा वाला कहेगा मेरा कर्जा माफ करो, रेहड़ी वाला कहेगा मेरा कर्जा माफ करो, दुकानदार कहेगा मेरा कर्जा माफ करो।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इंडस्ट्रियलिस्ट्स का क्यों माफ कर दिया?

श्री भजन लाल : माफ करने का अधिकार किसी को नही है। पैसा प्राइवेट बैंक में किस का जमा होता है, किसान का, आप लोगों का। पैसा माफ करने से किस का नुकसान है? हम सियासी आदमी हैं और अपनी सियासत के लिए हम लोगों को गुमराह नहीं करते। आपको लोगों को भी गुमराह नहीं करना चाहिए। ड्रामा आप जो करते हैं वह नहीं करना चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए जो असूल की बात हो। सरकार ने हमेशा रियायतें दी हैं।

श्री प्रमोद महाजन : उद्योगपति का 45 करोड़ रु० का कर्जा माफ किया है।

श्री भजन लाल : किसने किया?

श्री प्रमोद महाजन : आपकी सरकार ने किया।

श्री भजन लाल : उनके माफ होने का सवाल ही नहीं है। अगर उसने इंडस्ट्री के लिए लोन ले रखा है और वह देने की स्थिति में नहीं है तो जितनी भी उसकी फैक्ट्री की जमीन है, जायदाद है बकायदा सरकार नीलाम करती है, ओपन आक्शन कर के उसका पैसा वसूल करती है । इसी तरह से अगर किसान ने लोन ले रखा है और उसकी डैथ हो जाती है और उस लोन को देने वाला कोई नहीं है तो सरकार उस पैसे को माफ कर देती है । राईट आफ करती है ।

श्री प्रमोद महाजन : जो मरा हुआ है उससे तो पैसा वसूल ही नहीं किया जा सकता ।

श्री भजन लाल : उसका पैसा राइट आफ होता है । अगर कोई जीवित है और पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो जितनी भी उसके पास सम्पत्ति है, जितनी प्रोपर्टी है बकायदा उसका ओपन आक्शन किया जाता है और पैसा वसूल किया जाता है ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The point is the Minister raised a question whether the loan can be written off. Every year the banking institutions of the country write off Rs. 250 crores as bad debts and most of the defaulters are not peasants but the delinquent business houses of the country. Therefore, it is not true that loans are not written off. It is being done for rich people. Secondly, he has asked a question what the other Governments are doing. I can tell him for his knowledge that West Bengal has written off loans for the lowest category of peasants this year also. Therefore, Madam, this is not something new that we are asking from him. I would like to know from the honourable Minister. . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: My question is this: Is the honourable Minister aware that according to a survey conducted by the Reserve Bank of India, rural indebtedness is on the rise and it is alarmingly on the rise and, according to this study, ten per cent of the peasants have become landless and they have had to sell off very thing and they have become paupers and have added to the swelling ranks of poor landless agricultural labourers? Ten per cent of the peasantry has become landless and that is the impact of this indebtedness.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are not asking your question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, my question is what the Government proposes to do to tackle the problem of mounting indebtedness among the agriculturists of the country.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): Madam Deputy Chairman, I just want to seek your guidance. You took the decision that the next Question would be taken up... (*Interruptions*) ...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Madam, you have already allowed it... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, this is a unique case... (*Interruptions*)... This is a unique case of a Minister challenging the Chair. It is a unique spectacle... (*Interruptions*)... This is a unique spectacle.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I am not challenging the Chair. I just want to know whether a new precedent is going to be created. I just want to know whether, once you have taken up the next Question and closed the discussion on the previous one, you will permit another supplementary, you will permit a Member to put a supplementary. I just wanted a clarification.

THE DEPUTY CHAIRMAN: For the information of the honourable Minister, I would like to tell him that this question is very important and Members from both the sides desired to ask some more questions and the Minister also agreed

to that and, taking that into view, I said, "All right. It does not matter. I can allow some more Members".

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों के कुछ लोन माफ होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रियायतें फैक्ट्रियों को दी जाती हैं, जैसे अगर कोई बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाता है तो उनको कुछ रियायतें दी जाती हैं, बिजली में रियायत होती है। लेकिन ये अलग बातें हैं। जहां तक कर्ज वसूल करने का सवाल है, कर्जों के नाम पर वसूली बाकायदा की जाती है, चाहे फैक्ट्री को नीलाम ही क्यों न करना पड़े। सरकार नीलाम करके भी अपना पैसा वसूल करती है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की देहातों में देनदारी बढ़ गई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि देनदारी बढ़ने का क्या कारण है? देनदारी कैसे नही बढ़ेगी? मैं फिर सियासी बात, पौलिटिकल बात, कहना चाहता हूं। श्री देवीलाल जी जहां जाते हैं, यह बात करते हैं और वे दूसियों जगह जाते हैं और कहते हैं कि हरियाणा में कर्ज माफ हो गये... (**व्यवधान**)। और दूसरी स्टेट में कहते हैं कि यहां कर्ज माफ क्यों नहीं हुए? किसान सोचता है कि उसका कर्ज क्यों माफ नहीं हुआ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप कर्जों के संबंध में अपने प्रदेशों में ऐसी बात मत कीजिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बात मत कीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, इलेक्शन के पाइन्ट आफ व्यू से ऐसी बातें कही जाती हैं। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों की मेहरबानी से ये देनदारियां बढ़ी हैं। जो लोन लेता है उसको वह देना ही चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है, तभी मुल्क का कारोबार भी बढ़ेगा। आपस में आदान-प्रदान से ही कारोबार आगे बढ़ सकता है। और तभी देश का ढांचा ठीक ढंग से चल सकता है। सरकार रियायत देने की कोशिश कर सकती है और रियायत देती भी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके समय में किसानों की क्या हालत थी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज आप किसानों की बात करते हैं... (**व्यवधान**)

श्री नरेश सी. पुगलिया : महोदया, किसानों से हजारों रुपयों की वसूली की जा रही है इसलिए हमें सवाल करने की इजाजत दी जाए। महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो शेतकारी संगठन है वह किसानों में कर्जे मुक्त कराने के नाम पर सम्मेलन करता है। आपके जिले जलगांव में ही उन्होंने कर्जों के संबंध में कहा है। समस्त महाराष्ट्र में यह बात की जाती है। और उसमें नाजारी दाखिल करें तो पूरे महाराष्ट्र में 7 लाख किसानों ने ये फार्म भरे हैं सिविल कोर्ट में और प्रत्येक किसान से 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक उन्होंने फार्म भरने के पैसे लिए हैं और इस तरह से उन्होंने दो से ढाई करोड़ रुपये तक किसानों से वसूल किये हैं। ऐसा हमारे किसानों के साथ कर्ज मुक्ति के नाम पर, इस तरह के सस्ते नारों के नाम पर इस तरह किया जा रहा है। इस से कल अगर उनकी प्रापर्टी को कोई आक्शन करता है तो उससे किसानों को बहुत बड़ा नुक्सान होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसी चीप पापुलेरिटी जो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए शेतकारी संगठन द्वारा की जा रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे संगठनों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? ... (**व्यवधान**)... मेरी मांग है कि सरकार को ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। और महोदया, बी. पार्ट मेरा यह है कि मैं खुद किसान हूं और खासकर महाराष्ट्र और दूसरे प्रान्त में जो बड़े किसान हैं, जिन्होंने लाखों रुपया बैंक से लोन ले रखा है वे छोटे किसानों को सामने रखकर खुद इसका अधिक से अधिक फायदा उठाते हैं। इसलिए ये जो छोटे किसान हैं, जो दस एकड़ से नीचे के किसान हैं तो क्या उनको कर्जे के अंदर सरकार कोई रियायत देने जा रही है?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, इन्होंने जो बात कही उसमें बड़ा वजन है और बड़ा वैलिड प्वाइंट है..**(व्यवधान)** . . . कि किसानों को किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह से किसानों को गुमराह किया जाता है और किस तरह से लोगों को लूटा जाता है, इस नाम पर कि तुम्हारा कर्जा माफ करवा दिया जायेगा। इसके लिए उन से पैसा लिया जाता है चंदा वसूल किया जाता है और जैसा कि इन्होंने कहा करोड़ों रुपया वसूल किया गया । . . .**(व्यवधान)** . . .

श्री प्रमोद महाजन : शेतकारी संगठन पर पैसे खाने का आरोप सरासर गलत है . . .**(व्यवधान)**. . . महाराष्ट्र में अगर सात लाख किसानों ने फार्म भरकर दिए हैं तो इससे इस संगठन की ताकत क समझने की कोशिश करें, किसानों का दर्द समझने की कोशिश करें।. . .**(व्यवधान)** . . .

श्री नरेश सी. पुगलिया : कर्ज मुक्ति के नाम पर सात लाख किसानों . . .**(व्यवधान)** . . .आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : अगर सात लाख किसानों ने फार्म भरे हैं तो वहां दीवारों पर क्या लिखा है इसको पढ़ने की कोशिश करें । . . .**(व्यवधान)** . . .

श्री भजन लाल : जब आप कर्जे माफ करने की बात कहते हैं कि मैं लाखों का लोन माफ करवा दूंगा । आप के पास पहुंच जाये तो आप. . . **(व्यवधान)** . . .असलियत में कहना चाहिए कि किस तरह से लोगों को सियासी आदमी गुमराह करके ठगने की कोशिश कर रहे हैं । हम इस बात की जांच करवायेंगे । लोगों को आपत्ति इसमें है या नहीं । इस तरह से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है । जैसी अभी उत्तर प्रदेश में एक साहब खड़ा हो गया *कहते हैं या *कहते हैं या टिकैत नाम है पता नहीं क्या नाम है उनका । एक शरद जोशी खड़ा हो गया और हरियाणा में देवीलाल खड़ा हो गया । . . .**(व्यवधान)** . . . मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही । वे केवल भगवे कपड़े पहनते हैं ऐसा मैंने नहीं कहा . .**(व्यवधान)** . . .

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय इन्होंने *शब्द का प्रयोग किया है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

उपसभापति : अगर ऐसी बात होगी तो वह रिकार्ड में नहीं जायेंगी ।

SHRI JASWANT SINGH: Madam, . . . *(Interruptions)*

उपसभापति : आप सवाल लम्बा मत कीजिए । सवाल बहुत लम्बा हो रहा है ।

श्री जसवन्त सिंह : महोदया मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कहा कि कर्जों की माफी नहीं की जा सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने क्या कोई ऐसी गाइड लाइन नहीं दी हैं कि अगर सूखा पड़ता है, अगर लगातार तीन साल तक सूखा रहता है, तो जो रूरल इनडेटेडनेस है वह पूरी माफ की जायेगी ? क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है या नहीं है ? दूसरा राजस्थान में पिछले पांच सालों से सूखा पड़ रहा है लेकिन वहां रूरल इनडेटेडनेस को माफ नहीं किया जा रहा है इसका क्या कारण है ?

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, रिजर्व बैंक ने ऐसा नहीं कहा कि कर्जे माफ कर दिये जायें. . . **(व्यवधान)** . . . आप सुनने की बात करें । दूसरा इन्होंने कहा कि वहां पर सूखा पड़ा है इसलिये वहां कुछ रियायत करनी चाहिए । लगातार सूखा. . .

श्री जसवन्त सिंह : लगातार पांच साल से है ।

श्री भजन लाल : मैंने अर्ज किया कि. . .

*Not recorded.

श्री जसवंत सिंह : अगर इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं कि वहां पर लगातार ...

श्री भजन लाल : मैं समझ गया आपकी बात ...

श्री जसवन्त सिंह : तीन साल तक सूखा पड़ेगा रिजर्व बैंक की गाइड लाइंस हैं कि वहां कर्जे माफ किये जायेंगे । उसमें कोई आप्शन नहीं है ।

श्री भजन लाल : ऐसा बिल्कुल नहीं है । मैं आपको गाइड लाइन दिखाऊंगा कि वे क्या हैं... **(व्यवधान)** ... रिजर्व बैंक एक इन्डिपेन्डेन्ट बाडी है नहीं अलग से... **(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रिजर्व बैंक सरकार का डिपार्टमेंट है?... **(व्यवधान)**...

श्री भजन लाल: समझने की कृपा करें । आप यह जानने की कोशिश करें कि वह किस बात में इंडिपेन्डेन्ट है और किस बात में नहीं है । जब रीशैड्यूलिंग होगा तो उसके लिये उन्हें फाइनेंस के पास जाना पड़ेगा और इसके लिये जब तक फाइनेंस एग्री नहीं करेगा तब तक रिजर्व बैंक कैसे कर सकता है यह आप समझने की कृपा मेहरबानी से करें । ... **(व्यवधान)**...

SHRI DIPEN GHOSH: What is happening, Madam? Is Reserve Bank under Mr. Bhajan Lal? (*Interruptions*) The question is whether the Reserve Bank of India has issued the guidelines as Mr. Jaswant Singh has said.

श्री भजन लाल: ऐसा नहीं है कि माफ कर दिया जाएगा । और मैं कहता हूं कि ... **(व्यवधान)** दूसरा सवाल इस बात का है... **(व्यवधान)**...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Madam, the Minister is ignorant. The Reserve Bank of India is governed by the Reserve Bank Act. It is a central Act. Reserve Bank is not a department of the Government.

श्री भजन लाल : उपसभापति महोदया, रिजर्व बैंक ने माफ करने की कोई हिदायत नहीं दी है । लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि इसका रीशैड्यूलिंग करना चाहिए । जहां सूखा पड़ेगा तो शार्ट टर्म्स को लांग टर्म्स में और लांग टर्म्स को और भी लम्बा किया जाए । इसके लिए हमने कहा है कि जहां दो साल से लगातार सूखा पड़ा है वहां सात साल और जहां तीन साल से लगातार सूखा पड़ा है वहां दस साल की अवधि में लोन को लिया जाए ताकि सूखे की वजह से जो किसान इस समय मुसीबत में हैं उनकी ऐसे समय में इस तरह से मदद की जाए ।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: So far as the loan to the poor is concerned, there are no two opinions. As the hon. Minister has stated in his reply, as a matter of policy they are to be written off in cases of natural calamities. But loans are not taken by the poor people only. They are the rich people. They are corrupt people. They are muslmen. These people also take loans in the hope that their friends from the opositon sometimes may help them and they may not be required to repay the loans. I hold a brief for the poor people. The Minister says that it can be written off. Why don't you contemplate a situation in which well-to-do people, rich people, bullies and gunmen forcefully take loans? Are they also to be written off? Some of these loans are cornered by some anti-social elements also. In that case, why should the Government write off or waive such loans?

श्री भजन लाल : इन्होंने कोई सवाल पूछा नहीं है और जो भी इन्होंने पूछा है खुद ही अपनी बात का जवाब भी दे दिया है ।